

9
2.1.18

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुसा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, देवीधुरा (चम्पावत)
के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-404/XXIV(7)/2016-70(2)/15, दिनांक 16.08.2016 एवं संयुक्त परियोजना निदेशक, रुसा के पत्र संख्या 564(70)/रुसा/2017-18, दिनांक 18.12.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, देवीधुरा (चम्पावत) के निर्माण कार्यों हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित रू0 1047.28 लाख की धनराशि के सापेक्ष (सिविल कार्यों हेतु रू0 905.78 लाख + अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु रू0 141.50 लाख) रू0 5,73,28,334/- की धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है तथा रू0 4,73,99,666/- की धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष है, उक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 1,98,46,667/- (रू0 एक करोड़ अठानब्बे लाख छियालिस हजार छः सौ सड़सठ मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य रुसा के मानकानुसार हो तथा कार्य की अनुमोदित लागत रुसा के अन्तर्गत अनुमन्य लागत की सीमान्तर्गत हो अन्यथा की स्थिति में अगली किस्त स्वीकृत करने से पूर्व तदनुसार यथा आवश्यक कार्य में कटौती करते हुए यथा आवश्यक अनुमोदनोपरान्त कार्य की लागत अनुमन्य लागत के सीमान्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं रुसा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) को अवमुक्त की जायेगी तथा उनके द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- 5- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा योजना की डी0पी0आर0 में लिये गये अतिरिक्त कार्यों को हटाने हेतु कार्यदायी संस्था सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त करेगा।
- 6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 7- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- 8- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- 10- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करे।
- 11- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 12- स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 13- तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्ज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
- 14- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जायेगी तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किन्हीं भी कारणों से आगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- 15- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय की अनुदान संख्या 11 के पूंजीगत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0101-रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान-24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निर्गत निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

सं० 1083 (1)/xxiv(7)/2018-70(2)/15 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 3-जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4-निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 5-अपर परियोजना निदेशक, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून।
- 6-सम्बन्धित, कोषाधिकारी।
- 7-प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा-चम्पावत।
- 8-निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड।
- 9-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 10-वित्त अनु०-3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 11-परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हल्द्वानी-नैनीताल।
- 12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी०डी० बेलवाल)
उप सचिव।

